गैस्ट टीचर की दादागिरी के हवाले एक स्कूल

बल्लबगढ (म.मो.) यहां से करीब 14 किलोमीटर दूर फतहपुर तग़ा में स्थित है एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल यानी छठी जमात से बारहवीं तक का। इस स्कूल में पिछले कई बरसों से न तो कोई प्रिंसिपल है न क्लर्क। इस स्कूल से आसपास के चार गांवों के प्राथमिक स्कूल भी जुड़े हैं और धौज स्कूल के प्रिंसिपल के जिम्मे ये स्कूल भी हैं जो नाममात्र को ही देख पाते हैं। शहर से दूर और आने-जाने का साधन मात्र ऑटो होने के चलते कोई भी यहां तैनात होकर राज़ी नहीं। जिसकी भी यहां तैनाती होती है वह राजनेताओं की चापलूसी करके यहां से निकल भागता है।

दसवीं तक का गणित पढाने के लिये यहां सुबोध नामक एक गैस्ट टीचर को रखा गया है। वह कई बरसों से यहां तैनात है। परन्तु उसने आज तक कभी किसी बालक को गणित नहीं पढाया। उसके ज़िम्मे है स्कूल की क्लर्की। कुल 18 शिक्षकों और 350 बच्चों के इस स्कूल में कोई बहुत ज्यादा क्लर्की का काम नहीं, परन्तु सुबोध न तो क्लर्की ढंग से करता है और पढाने का तो बिल्कुल ही नहीं। क्लर्क होने के नाते अपना वेतन तो हर माह की पहली तारीख को निकाल लेता है बाकी स्टाफ़ का वेतन दो-तीन माह तक लम्बित रखता है और जब निकालता भी है तो बड़ा अहसान करके निकालता है। इसी क्लर्की के नाम पर वह अक्सर स्कूल से नदारद रहता है और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बल्लबगढ की ब्रांच के पास स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर बैठा रहता है।

गतांक में पाठकों ने पढा था कि शिक्षाधिकारियों के दफ़्तरों में शिक्षकों के वे नियमित काम भी नहीं होते जो बाबुओं व अधिकारियों को स्वत: करके बजरिया डाक स्कूलों में भेज देने चाहियें। इसका एक नमूना भी इस स्कूल में देखने को मिला। करीब 10 शिक्षकों की सर्विस बुक लम्बित है। इसे पूरा कराने के नाम पर सुबोध ने 200 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये की वसूली इन सभी शिक्षकों से इसी माह की है। उसका कहना है कि यह रकम वह आगे सम्बन्धित बाबू को दे आया। इस काम के बाद जुलाई 2014 से इन सबकी वेतनवृद्धि लगनी है। उसके लिये 500 रुपये प्रति शिक्षक के हिसाब से 5000 रुपये अलग से लगेंगे जो वह दफ़्तर में एस ओ (ज़िला शिक्षाधिकारी कार्यालय में सेक्शन अफ़सर) को देकर आयेगा।

ऐसा नहीं है कि यह गोरखधंधा किसी एक-आध सकूल में चल रहा हो; लगभग सभी में चल रहा है। तमाम अफ़सर व राजनेताओं को इसका न केवल ज्ञान है बल्कि उनके संरक्षण के बिना इसका चल पाना संभव नहीं। जिन स्कूलों में शिक्षक खुद रिश्वत देकर अपना काम निकाल रहे हों वहां बच्चे क्या सीखेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भ्रष्टाचार-मुक्त हरियाणा के नारे का क्या मतलब निकालेंगे? इस स्कूल का मुख्य द्वार तो बहुत शानदार बना है। लेकिन इसका होना ना होना बराबर है क्योंकि स्कूल की चारदिवारी तो है ही नहीं। है ना मजे की बात। अब स्कूल की चारदिवारी का बजट आ गया बताते हैं और निर्माण कार्य का ठेका भी कामचलाऊ प्रिंसिपल (धौज) ने किसी को दे दिया है। इस बात से एस एम सी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के कुछ ठोंडों को काफ़ी तकलीफ़ है। इस कमेटी का एक ठोंडा है अनवर। उसने तो स्कूल स्टाफ़ के सामने ही कह दिया कि उसके होते प्रिंसिपल किसी और को ठेका कैसे दे सकता है? वास्तव में वह खुद इस ठेके के नाम पर अपनी जेब भरने के चक्कर में है।

संदर्भवश पाठक जान लें कि स्कूलों पर जनता की निगरानी बनाये रखने के नाम पर सरकार ने एस एम सी का प्रावधन किया है। इसके सदस्यों की संख्या स्कूल में पढने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है। यह 5 से लेकर 21 तक कुछ भी हो सकती है लेकिन इसका चेयरमैन स्कूल का प्रिंसिपल ही होता है। सदस्यों में आमतौर पर सरपंच, पार्षद आदि होते हैं। फतहपुर तगा के इस स्कूल में एस एम सी सदस्यों खासकर अनवर का तो स्थाई डेरा लगा ही रहता है जो स्कूल संचालन में किसी प्रकार के सहयोग की ऊपेक्षा पार्टीबाज़ी व अड़ंगेबाज़ी को ही बढावा देता है।

बिहार में लालू के चरवाहा स्कूलों की याद भी इस स्कूल को देख कर ताज़ा हो जाती है क्योंकि बच्चों के साथ-साथ उनकी बकरियां भी स्कूल में उनके साथ ही आती हैं, खासतौर पर आधी छुट्टी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही आती हैं। स्कूल की अधिकांश खिड़कियां व बैंच टूटे पड़े हैं। कहते हैं कि बच्चे उखाड़ कर ले जाते हैं। यदि यह सही है तो बच्चों को पढाने वाले शिक्षकों व एस एम सी के सदस्य सवालों के घेरे में आते हैं।

सरकार शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ़ व सुविधायें उपलब्ध कराने की बजाय लाखों रुपये बतौर खैरात यहां बांट देती है। गांव वाले अपने बच्चों को यहां पढने के लिये नहीं बल्कि दलिया व खिचड़ी खाने तथा वजीफ़े के नाम पर खैरात के चन्द रुपये बटोरने के लिये भेजते हैं। पीने वाले इन रुपयों की शराब पी जाते हैं और बच्चे अन्तत: बकरियां चराने वाले चरवाहे ही बन कर रह जाते हैं। इन हालात में परीक्षा परिणाम यदि निम्न स्तर के आ रहे हैं तो क्या ग़लत है। कहने की जरूरत नहीं कि यदि किसी देश अथवा समाज का सत्यानाश करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस कर दो और यह काम देश की सरकारें पूरी ईमानदारी व लगन से कर रही हैं।

बिन रिश्वत सब सूना....

वेतन वृद्धि शिक्षक के वेतन में जोड़ कर उसका वेतन तय किया जाता है। सर्विस बुक को भरने का काम क्लर्क करता है, जिस पर स्कूल मुखिया के हस्ताक्षर होते हैं। परन्तु शायद ही किसी शिक्षक की सर्विस बुक बिना रिश्वतखोरी के भरी जाती हो। और जब स्कूल मुखिया ही काणा हो तो क्लर्क क्यों परवाह करने लगा?

सर्विस बुक पूरी होने के बाद यह जाती है डी ई ओ (ज़िला शिक्षाधिकारी) कार्यालय में। यहां बैठा। एस.ओ. (सेक्शन अफ़सर) शिक्षकों के वेतन में सालाना वृद्धि जोड़ कर उसे तय करता है। इसके लिये शिक्षकों को अलग से डी ई ओ कार्यालय के चक्कर लगाने के अलावा एस.ओ, को एक तयशुदा रिश्वत देनी होती है। किसी भी शिक्षक का कोई मेडिकल या अन्य बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक सम्बन्धित बाबू को तय दर से कमीशन न दिया जाय।

सभी शिक्षकों को एल.टी.सी. के नाम पर हर तीन साल बाद एक माह का वेतन मिलता है। यह भी केवल तभी मिल सकता है जब सम्बन्धित बाबू को एक से दो हज़ार तक (वेतन अनुसार) की रिश्वत दी जाय। ऐसा नहीं है कि यह सब लेन-देन कोई चोरी-छिपे होता हो, बिल्कुल चौड़े में और मेज पर मुक्का मार कर होता है। हां अपवादस्वरूप वहां नहीं होता जहां मजबूत व ईमानदार शिक्षाधिकारी तैनात हों, जो बाबूओं से काणे न हों जो निकम्मे व भ्रष्ट बाबुओं को धमका सकें। वहां ये बाबू ठीक से काम करते हैं और सम्बन्धित शिक्षक भी ठीक से पढा पाते हैं।

पुलिस, तहसील, हूडा आदि विभागों तो भ्रष्टाचार मुक्त करने में तो कोई दिक्कत आ सकती है, परन्तु शिक्षा जैसे महकमे को भी खट्टर व मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने में क्यों विफ़ल हो रही है यह गंभीर प्रश्न है।

कोई शिक्षक चाहे भी तो पढाना मुश्किल

इसी सकूल में पिछले दिनों मुकेश नामक गणित का एक अध्यापक कैथल से तबादला होकर आया। तिगांव क्षेत्र के भुआपुर गांव के रहने वाले मुकेश ने सकूल में आते ही पूरी ईमानदारी व मेहनत से बच्चों को पढाना शुरू कर दिया। उन्हीं की तरह मेहनत करने वाले अन्य शिक्षकों को भी यह अच्छा लगा, परन्तु गणित अध्यापन के नाम पर ठगी मार रहे सुबोध को यह सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उसे डर सताने लगा कि इस तरह तो पढाने वाले अध्यापकों का गठबंधन मजबूत हो जायेगा तो उस जैसे निकम्मे के लिये कभी भी मुसीबत खड़ी हो सकती। बच्चों के बीच भी यदि ये लोकप्रिय हो गये तो मुसिबत और भी बढ सकती है।

इस संभावित मुसिबत की पेशबंदी करते हुए सुबोध ने मुकेश पर पहले तो तरह-तरह के वाकबाण छोड़ने शुरू किये, जब उससे भी बात न बनी तो 15 मई को सुबोध ने मुकेश को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जाहिर है जवाबी कार्यवाही मुकेश को भी करनी पड़ी। ऐसे में दो अध्यापकों के बीच होने वाले इस डंडा युद्ध को देखने के लिये सारे बच्चे व स्टाफ़ जमा हो गया। अधिकांश स्टाफ़ ने मुकेश का साथ देते हुए इस झगड़े को बन्द कराया। सुबोध ने तुरंत गांवों में सूचना भेजकर अपने समर्थक ग्रामीणों को बुला लिया। लेकिन उनके आने से पहले स्कूल की छुट्टी कर दी गयी जिससे झगड़ा आगे नहीं बढ पाया।

ग्रामीणों में सुबोध की पैंठ का एक बड़ा कारण यह बताया गया है कि सरकार द्वारा अनुसूचित व पिछड़ी जातियों के बच्चों को दिये जाने वाले वजीफ़े का वितरण 'क्लर्क' के नाते सुबोध करता है। भोले-भाले ग्रामीण इसे सुबोध का ही एहसान मान कर उसके आभारी हो जाते हैं और उसके द्वारा किसी भी तरह इस्तेमाल किये जाने को तत्पर रहते हैं।

प्रशासनिक ढिलाई व हिन्दुत्व की आग में झुलसा गांव

बल्लबगढ़ (म.मो.) करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव अटाली की कुल आबादी करीब छ: साढे छ: हज़ार है। इसमें 1000 के करीब मेव (मुसलमान) है। शेष आबादी जाट बाहुल्य है। सैंकड़ों साल से दोनों समुदाय बेमिसाल भाइचारे के साथ रहते हुए अपने-अपने काम-धंधे, मुख्यत: खेती-किसानी करते आये हैं।

लेकिन मई माह के दूसरे पखवाड़े में यहां साम्प्रदायिकता की आग भड़क उठी। कुछ मुस्लिम घर व उनके बोंगे-बिटोड़े जला दिये गये। पुलिस एवं प्रशासन की घोर लापरवाही एवं ढिलाई के चलते तनाव इतना बढता चला गया कि तमाम अल्पसंख्यक गांव से पलायन करके थाना शहर बल्लबगढ़ में आ जमे और खौफ़ इतना कि वहां से जाने का नाम नहीं लेते। ये लोग गांव में वापस जायं तो जांय भी कैसे जब दबंगों की दबंगई, गांव में पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी के बावजूद रूकने में नहीं आ रही।

झगड़े की शुरूआत अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी मस्जिद के निर्माण कार्य को शुरू करने से हुई। यह ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड यानी मुसलमानों की ही घोषित है। पिछले अनेक बरसों से ये लोग इस जगह पर नमाज पढते आ रहे हैं। धनाभाव के चलते इस जगह पर टीन-टप्पड़ डाल कर ही ये लोग अपना काम चलाते आ रहे थे। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर जब इन्होंने इस स्थल पर पक्का निर्माण करना चाहा तो दबंगों

ने अड़ंगा लगा दिया। मामला न्यायालय पहुंचा। करीब 5 साल के बाद न्यायालय ने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दे दिया तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। शुरू करते ही कुछ शरारती तत्वों ने अड़ंगेबाज़ी व तोड़-फ़ोड़ शुरू कर दी जो होते-हवाते मार-पीट व आगजनी तक पहुंच गयी।

ध्यान रहे कि 5 वर्ष पूर्व इस काम को रोकने का काम तत्कालीन सरपंच प्रह्लाद ग्रुप ने किया था। अब जब ये लोग कोर्ट से जीत कर आ गये तो मौजूदा सरपंच राजेश ने इनसे तो कह दिया कि निर्माण कार्य शुरू करो तथा प्रह्लाद ग्रुप को उकसा दिया कि बनने मत दो। यानी दोनों ग्रुपों को एक साथ साधने का प्रयास किया। विदित है कि प्रह्लाद पूर्व विधायक रघुबीरा से तथा राजेश कर्ण दलाल से जुड़ा है। ये दोनों नेता इस दंगे के माध्यम से अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं।

यदि इस देश में सरकार और क़ानून नाम की कोई चीज़ हो तो यह कोई समस्या ही नहीं है। पंगु सरकार एवं नाकारा प्रशासन के चलते गत एक पखवाड़े से पूरा गांव पुलिस छावनी बना हुआ है। छ: ज़िलों से करीब 600-700 पुलिस कर्मी बेमतलब वहां तान कर खड़े कर रखे हैं। मीटिंगों के दौर पर दौर चल रहे हैं। सीधी सी बात को कोई समझना नहीं चाहता कि जब एक वर्ग अपनी जगह पर कोई निर्माण कार्य

शेष पेज सात पर

सब से 'सुरक्षित' जगह जान कर थाना कोतवाली के निकट करी हत्या व लूट

फ़रीदाबाद (म.मो.) हत्या व लूट की वारदात हो जाना, अपराध नियन्त्रण व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह तो लगाता है, परन्तु उससे भी गंभीर व खतरनाक दिनदहाड़े थाने के सामने वारदात का हो जाना है। ठीक वैसे ही जैसे सांप का बगल से गुजर जाना खतरनाक तो है परन्तु उसका पेट के ऊपर से गुज़र जाना कहीं ज़्यादा खतरनाक है।

दिनांक 25 मई को बल्लबगढ-सोहना रोड पर गोंछी गांव के निकट स्थित सांई पेट्रोल पम्प के दो कर्मचारी करीब 22 लाख रुपये, नीलम-बाटा रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा कराने मोटरसाइकिल से जा रहे थे। समझा जाता है कि मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरे पेट्रोल पम्प से उनके पीछे लग लिये थे। करीब 5 किलोमीटर लम्बे रास्ते में, वारदात को अंजाम देने के लिये उन्हें सबसे बढिया एवं सुरक्षित जगह थाना कोतवाली से करीब 25 मीटर पहले (बाटा की ओर) लगी।

लुटेरों ने पहले पम्प कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंकने का प्रयास किया। असफ़ल होने पर उनकी बाइक में टक्कर मार कर गिरा दिया। बाइक की डिग्गी से कैश निकालने का प्रयास किया। विरोध करने वाले कर्मी को छाती में गोली मार कर कैश ले भागे। घायल कर्मी की उसी रात मौत हो गयी।

वारदात तो हो गयी सो हो गयी। पहले भी होती थीं और आगे भी होंगी। विचारणीय विषय तो अपराधियों के बुलंद होते होंसले का हैं जो थाने के सामने वारदात करने में नहीं हिचके। जो अपराधी, पुलिस एवं कानून से खौफ़ खाते थे अब इतने बेखौफ़ कैसे हो गये? पुलिस एवं कानून का इकबाल इस कदर रसातल में कैसे धंस गया?

यह स्थिति कोई एक दिन में यकायक नहीं आ गयी है और न ही एक दिन में सुधरने वाली है। इसके लिये किन्हीं दो-चार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा देने या उन्हें बदल देने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। बदलने की जरूरत है तो उस भ्रष्ट व्यवस्था को जिसने सिपाही से लेकर अफ़सरों तक की भर्ती का आधार योग्यता की अपेक्षा रिश्वत, रिश्तेदारी अथवा सिफ़ारिश आदि रह गये हैं। भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग का गिरता स्तर और ट्रेनिंग के बाद मलाईदार तैनाती के लिये जुगाड़बाज़ी।

बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पिछले एक-डेढ महीने में इसी शहर की पुलिस के 4-5 अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह जैसे फेंटा गया वह क्या दर्शाता है? डी सी पी मुख्यालय को पहले एन आई टी लगाया, फिर हटाया, फ़िर लगाया और अन्त में हटा ही दिया। इसी एन आई टी में ए सी पी लगने के लिये जो छीना-झपटी हो रही है, वह ठीक वैसी ही लगती है जैसे एक शिकार को हड़पने के लिये तीन-तीन बिल्लियां लड़ रही हों। इनको लड़ाने वाले राजनेताओं ने तमाशा देखते हुए एक पोस्ट पर तीनों को ही तैनात कर दिया। ऐसा ही कुछ ए सी पी तिगांव के साथ हो रहा है। उन्हे वहां से हटा कर डी एस पी रेलवे फ़रीदाबाद लगाया, फ़िर ए सी पी मुख्यालय और अब अन्त में फ़िर से ए सी पी तिगांव लगाया गया। आखिर यह सब क्या है?

यह सब केवल निचले स्तर पर ही नहीं हो रहा, ऊंचे स्तर पर यानी ज़िलों के एस पी अथवा कमिश्नर, डी आई जी, आई.जी व डी जी स्तर पर तो तैनातियों की इस छीना झपटी का चेहरा बहुत ही कुरूप हो चुका है। राज्य के डी जी पी पद की तैनाती पाने के लिये बड़े अफ़सर लोग क्या-क्या कर जाते हैं आम आदमी सोच भी नहीं सकता। फ़िर ऐसे में सिपाही-थानेदार स्तर के अफ़सरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? पी सी आर की जिप्सी में बैठा जवान इसी सोच में रहता है कि कब कोई मुर्गा फ़ंसे।

यदि किसी वारदात की खबर आ जाये तो उसकी कोई रूचि नहीं होती कि वह तुरन्त घटना स्थल की ओर भागे, उसकी कोई रूचि नहीं होती कि वह अपराधियों पर नज़र रखे। हर पुलिसकर्मी की कोशिश रहती है कि किसी भी जुगाड़बाज़ी से उसकी तैनाती किसी मलाईदार जगह पर हो जाय। उसका ध्यान केवल और केवल अधिक से अधिक उगाही पर रहता है न कि अपराधियों व अपराध नियन्त्रण पर।

जब तक राजनेता इस व्यवस्था को दुरूस्त नहीं करेंगे अपराध तो यूं ही थाने-चौकियों के सामने होते रहेंगे चाहे किसी को हटा दो और किसी को लगा दो।